

**नेशनल फंडेशन आफ इंडस्ट्रीयल  
कोआपरेटिक्स**

4945. श्री मोतीभाई चौधरी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल फंडेशन आफ इंडस्ट्रीयल कोआपरेटिक्स के लेखों की अनेक वर्षों से लेखापरीक्षा न कराये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) अनियमितताएं करने के कारण इसके कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है; और

(ग) क्या वर्तमान प्रबन्ध-निदेशक द्वारा कार्यभार संभाले जाने के बाद से इसके कार्य-करण में कोई सुधार हुआ है ?

**उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) :**

(क) नेशनल फंडेशन आफ इंडस्ट्रीयल कोआपरेटिक्स के लेखाओं की लेखा परीक्षा 30 जून, 1973 तक की गई है। वर्ष 1973-74 के लेखों की लेखा परीक्षा की जा रही है और उसे शीघ्र ही अंतिम रूप दिये जाने की आशा है। फंडेशन के लेखों की लेखा परीक्षा में देरी होने का कारण फंडेशन की लेखा शाखा में कर्मचारियों की कमी होना है। वर्ष 1976-77 की अवधि में भारत सरकार ने लेखा शाखा में यथोचित कर्मचारी रखने के लिए अनुदान का प्रावधान किया है तब से इस संबंध में कुछ सुधार हुआ है।

(ख) अनियमितताएं करने के कारण फंडेशन के किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है।

(ग) वर्ष 1976-77 में फंडेशन का कुल कारोबार 35.87 लाख रुपये का हुआ जबकि वर्ष 1975-76 का कारोबार 17.92 लाख रुपये का हुआ था। फिर भी फंडेशन में अब भी भारी हानियां हो रही हैं। फंडेशन के कार्य संचालन में अनेक अनियमितताएं जिनमें से कुछ तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक के काम करने के ढंग से संबंधित हैं,

सरकार की जानकारी में आ गई हैं जिनकी इस समय जांच की जा रही है।

**Increase in Prices by Brylcream**

4946. SHRI VAYALAR RAVI:

SHRI K. KUNHAMBUR:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) total number of times the Brylcream has increased its prices during the last two years and the details thereof; and

(b) steps taken by Government to prevent unreasonable price increase of this company at the expense of the consumers?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) Government do not maintain data on the prices of non-essential items like Brylcream.

(b) Does not arise.

**Enforcement of Section 25 of Cr. P.C.**

4947. SHRI AHSAN JAFRI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that though the Cr. P. Code '73 has come into force since last three years, the State Governments have not enforced section 25 of the Act by putting Assistant Public Prosecutors under Legal Department instead of Police Department as contemplated by the Act; and

(b) if so, what action has been taken so far and what future action the Ministry will take in this respect?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH):